दीपक गुलाटी

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2322/2010)

20 मई, 2013

[डॉ. बी.एस. चौहान और दीपक मिश्रा, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 धाराएं. 376, 365 और 90- बलात्कार और सहमति से यौन संबंध- के बीच अंतर- आरोप है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री को फुसलाया, उसका गलत तरीके से सदोष परिरोध किया और उससे शादी करने के वादे के बदले में उसके साथ यौन संबंध बनाए- नीचे के न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता को धारा 365 और 376 भादस में दोषी ठहराया गया- को चुनौती-अभिनिर्धारित-इस तरह के मामले में, न्यायालय को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था, या उसका दुर्भावनापूर्ण आशय था, और केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए उसने झूठा वादा किया है, जो बाद में धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है- केवल एक वादे को तोड़ना, और एक झूठा वादा पूरा न करने के बीच अंतर- एक आरोपी को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, अगर उसका इरादा दुर्भावनापूर्ण था, और उसका गुप्त इरादा था। भादस की धारा 90 लड़की के कृत्य, को पूरी तरह से माफ करने और आरोपी पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए काम में नहीं ली जा सकती है, जब तक कि न्यायालय को यह आश्वासत नहीं कर दिया जाए कि शुरू से ही, आरोपी वास्तव में उसके साथ शादी का कोई इरादा नहीं रखता था -हस्तगत मामले में, अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता से शादी करने के लिए स्वेच्छा

से, अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया था- प्रासंगिक समय पर उसकी उम्र 19 वर्ष थी और वह अपीलकर्ता से अपनी शादी से जुड़ी जटिलताओं और मुद्दों को समझने में सक्षम थी। अभियोक्त्री कई मौकों पर स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ अंतरंग हुई और उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की- वास्तव में, वह अपीलकर्ता के साथ आगे बढ़ रही थी ताकि वे दोनों न्यायालय में शादी कर सकें, तब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया- इस प्रकार, अभियोक्त्री द्वारा "शादी के झूठे वादे" के उठाये गये आरोप में कोई आधार नहीं है -

अपीलकर्ता के विरुद्ध धोखे/बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। उसकी दोषसिद्धि को रद्द किया गया- साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 114ए अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू 8 की 19 वर्षीय पुत्री को फुसलाया, उसे गलत तरीके से सदोष परिरोध किया और उससे शादी करने के वादे के बदले में उसके साथ यौन संबंध बनाए। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और भादस की धारा 365 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा और भादस की धारा 376 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई इसलिए यह अपील की गई।

इस वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या अपीलकर्ता का शुरू से ही पीड़िता को धोखा देने का आशय था और शादी के झूठे वादे पर पीड़िता की सहमति प्राप्त की गई थी।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 ए में प्रावधान किया गया है कि यदि अभियोक्त्री गवाही देती है कि उसने अपनी सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने वास्तव में ऐसी सहमति नहीं दी थी। हस्तगत मामले के तथ्य इस बात की अनुमति नहीं देते कि अधिनियम 1872 की धारा 114.ए के प्रावधानों को लागू किया जाए। (पैरा 15), (554.जी.एच, 555.ए)

1.2. हालाँकि सहमति अभिव्यक्त या निहित हो सकती है, जबरदस्ती या गुमराह करके हो सकती है, स्वेच्छा से या धोखे से प्राप्त की जा सकती है। सहमति एक कार्य का कारण है, जिसमें विचार-विमर्श शामिल है, दिमाग एक तराजू की तरह प्रत्येक पक्ष की अच्छाई और बुराई को तौलता है। बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है और इस तरह के मामले में, न्यायालय को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था, या उसका दुर्भावनापूर्ण आशय था, और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, जो बाद में धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के दायरे में आता है। महज एक वादे का तोड़ना और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर है।

इस प्रकार न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक चरण में ही शादी का झूठा वादा किया था और क्या इसमें शामिल सहमति यौन संबंध की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह समझने के बाद दी गई थी। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री आरोपी के प्रति अपने प्यार और आशक्ति के कारण संभोग करने के लिए सहमत हो, न कि केवल आरोपी द्वारा उसके साथ की गई गलत प्रस्तुति के कारण, या जहां, एक आरोपी उन परिस्थितियों के कारण जिनकी उसने कल्पना नहीं की थी, या जो उसके नियंत्रण से परे थी, ऐसा करने का हर इरादा होने के बावजूद, वह उससे शादी करने में असमर्थ था। ऐसे मामलों में अलग तरह से

व्यवहाँर किया जाना चाहिए। किसी आरोपी को बलात्कार के लिए तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि आरोपी का इरादा दुर्भावनापूर्ण था और उसके छुपे हुए इरादे थे। (पैरा 18), (556- ए-एफ)

1.3. यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर, यानी शुरुआती चरण में, ही आरोपी का पीड़िता से शादी करने के अपने वादे को निभाने का कोई इरादा नहीं था। निस्संदेह, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब एक व्यक्ति नेक इरादा रखता हो परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से शादी करने में असमर्थ हो। भविष्य की अनिश्चित तारीख के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने में विफलता, के कारण जो उपलब्ध साक्ष्यों से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, हमेशा तथ्य की गलत धारणा नहीं होती है। गलत धारणा शब्द के अर्थ में आने के लिए वास्तव में, तथ्य की तत्काल प्रासंगिकता होनी चाहिए। " ऐसी स्थिति में भादस की धारा 90 की उपधारणा को किसी लड़की के कृत्य को पूरी तरह से माफ करने और दूसरे पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है। दूसरा, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त नहीं हो जाता है कि शुरू से ही, आरोपी ने वास्तव में उससे शादी करने का कभी इरादा नहीं किया था। (पैरा 21), (558- ए- डी)

उदय बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 2003 एससी 1639:2003 (2) एससीआर 231; दिलीप सिंह उर्फ दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य एआईआर 2005 एससी 203:2004 (5) पूरक। एससीआर 909; येदला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 11 एससीसी 615:2006 (6) पूरक। एससीआर 760; प्रदीप कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। एआईआर 2007 एससी 3059:2007 (9) एससीआर 58 और एन. जलाडु, आरई आईएलआर (1913) 36 मद्रास 453-संदर्भित।

2. हस्तगत मामले में, पीड़िता ने अपीलकर्ता से शादी करने के लिए अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया था। प्रासंगिक समय पर उसकी उम्र 19 वर्ष थी और इसलिए, वह अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी से जुड़ी जटिलताओं और मुद्दों को समझने में सक्षम थी। उसके द्वारा कथित की गई घटनाओं के संस्करण के अनुसार, अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता को उसके द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल किया था, यह पूछने के लिए कि वह उससे उस स्थान पर क्यों नहीं मिला जो उनके द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था। उसने काफी देर तक उसका इंतजार भी किया और जब वह आखिरकार आ गया तो वह उसके साथ कर्ण झील पर गई जहां उन्होंने संभोग किया। उसने इस स्तर पर कोई आपत्ति नहीं जताई और किसी से कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद, वह अपीलकर्ता के साथ कुरुक्षेत्र भी गई, जहां वह उसके रिश्तेदारों के साथ रही। यहां भी, अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ अंतरंग हो गयी। फिर, किसी कारण से, वह अवैध रूप से कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने चली गई और एक बार फिर बिड़ला मंदिर में अपीलकर्ता के संपर्क में आई। इसके बाद, वह अंबाला जाने के लिए अपीलकर्ता के साथ कुरूक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर भी गई, ताकि वे दोनों अंबाला में न्यायालय में शादी कर सकें। हालांकि, यहां उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। यदि अभियोक्त्री वास्तव में अपीलकर्ता से शादी करने के लिए अंबाला जा रही थी, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पूरी तरह से स्थापित है, ऐसे में कोई भी यह समझने में असमर्थ है कि किस आधार पर अभियोक्त्री द्वारा शादी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया गया है। उपर्युक्त तथ्य की स्थिति के आलोक में कोई भी उन परिस्थितियों को समझने में असमर्थ है जिनमें अपीलकर्ता के खिलाफ धोखे/ब्लात्कार का आरोप लगाया जा सकता है। [पैरा 23,24] [559-ए.एफ]

3. अपीलकर्ता, जो पहले ही 3 साल से अधिक की सजा काट चुका है, संदेह का लाभ पाने का हकदार है। उसकी दोषसिद्धि और नीचे के न्यायालयों द्वारा दी गई सजा को रद्द किया गया है। [पैरा 25, [559-जी-एच]

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत

2003 (2) एससीआर 231	संदर्भित	पैरा 16
2004 (5) पूरक एससीआर 909	संदर्भित	पैरा 16, 19
2006 (6) पूरक एससीआर 760	संदर्भित	पैरा 16
2007 (9)एससीआर 58	संदर्भित	पैरा 16, 20

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 2322/2010

उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के सीआरए नंबर 960/1998 एसबी (ओ एंड एम) में निर्णय और आदेश दिनांकित 28.01.2010 से।

अपीलकर्ता की ओर से अमित पवन।

प्रत्यर्थी की ओर से कमल मोहन गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय,न्यायाधीश डॉ. बी.एस. चौहान, जे. के द्वारा पारित किया गया।

1. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सीआरए नंबर 960/1998 एसबी में पारित दिनांक 28.1.2010 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल के दिनांक 13.11.1998 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई,

सत्र मामला संख्या 7/1995 में पारित हुआ था, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 365 और 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

(इसके आगे भादस के रूप में संदर्भित किया गया है।) धारा 365 भादस के तहत 2,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और भादस की धारा 376 के तहत सात साल की कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ इस प्रकार है-

(i) अपीलकर्ता और गीता, अभियोक्त्री उम्र 19 वर्ष, सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, करनाल में 10+2 की छात्रा, कुछ समय से एक-दूसरे को जानते थे। अपीलकर्ता उसके साथ अंतरंग संबंध विकसित करने के प्रयास में उसके स्कूल के सामने उससे मिल रहा था। 10.5.1995 को अपीलकर्ता ने उसे शादी करने के लिए अपने साथ कुरूक्षेत्र चलने के लिए प्रेरित किया और वह सहमत हो गई। करनाल से कुरूक्षेत्र के रास्ते में अपीलकर्ता उसे कर्ण झील (करनाल) ले गया और झाड़ियों के पीछे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया। इसके बाद, अपीलकर्ता उसे कुरुक्षेत्र ले गया, 3-4 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के साथ रहा और उसके साथ बलात्कार किया।

(ii) अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री को 4 दिनों के बाद बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वह कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में चली गयी, और कुछ दिनों तक वहाँ रही। छात्रावास के वार्डन को संदेह हुआ और उसने पिड़िता से पूछताछ की। इस प्रकार अभियोक्त्री ने घटना के बारे में वार्डन को बताया। जिसने उसके पिता को सूचित किया। इस बीच, पीड़िता ने छात्रावास छोड़ दिया और एक मंदिर में चली गई। जहां वह एक बार फिर अपीलकर्ता से मिलीं। यहां अपीलकर्ता ने उसे शादी करने के

लिए अपने साथ अंबाला चलने के लिए मना लिया। जब वे अम्बाला बस स्टैंड पहुंचे तो उन्होंने पीड़िता के पिता को पुलिस के साथ वहाँं मौजूद पाया। अपीलकर्ता को पकड़ लिया गया।

(iii) पीड़िता के पिता बलदेव राज सोनी ने दिनांक 16.5.1995 को धारा 365 और 366 भादस के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में धारा 365 और 376 भादस के तहत में परिवर्तित कर दिया गया।

(iv) अभियोक्त्री की दिनांक 17.5.1995 को चिकित्सकीय जांच की गई। उसके मजिस्ट्रेट द्वारा 20.5.1995 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके द.प्र.स. के रूप में संदर्भित) की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था। अनुसंधान पूरी करने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के मद्देनजर, सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 3.5.1996 के आदेश के तहत धारा 365 और 376 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

(v) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 13 गवाहों को परिक्षित करवाया गया और उसके मद्देनजर, सत्र न्यायालय ने दिनांक 13.11.1998 के निर्णय और आदेश के द्वारा अपीलकर्ता को भादस की धारा 365, 376 के तहत दोषी ठहराया और उसे उक्त आरोपों के लिए (ऊपर उल्लेख की गई) सजा सुनाई।

(vi) व्यथित, अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में आपराधिक अपील संख्या 960/1998 एसबी (डी एंड एम) दायर की जिसे दिनांक 18.11.1998 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह अपील।

3. अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके मद्देनजर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कमल मोहन गुप्ता की मदद से न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सामग्री की जांच की और दोनों आक्षेपित निर्णयों का अध्ययन किया।

4. अभियोक्त्री (पीडब्लू 7) का बयान दिनांक 20.5.1995 को द.प्र.स. की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह अपीलकर्ता के साथ शादी करने के लिए गई थी और इस उद्देश्य के लिए उसने (एक दस्तावेज) अपनी उम्र के प्रमाण के रूप में अपने स्कूल से एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। उक्त तिथि को अर्थात 10.5.1995 को, चूंकि अपीलकर्ता पूर्व-निर्धारित स्थान पर पहुंचने में असमर्थ था, अभियोक्त्री ने उसके द्वारा दिए गए नंबर पर फोन किया। उसने आगे यह भी अभिकथन किया है कि अपीलकर्ता ने उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था, लेकिन वह शादी से पहले ऐसा करने के लिए सहमत नहीं थी जब वे कुरूक्षेत्र पहुंचे और वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ रुके, तो अपीलकर्ता ने उसके साथ 3 दिन तक शारीरिक संबंध बनाए। चौथे दिन, अपीलकर्ता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार, वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास में चली गई थी, जहाँ वह विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बहाने रुकी थी। हालाँकि, विश्वविद्यालय कर्मीयों को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछताछ करने के बाद उसके घर पर फोन किया। इसके बाद उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और कुरूक्षेत्र के बिड़ला मंदिर चली गई, जहां उसकी अपीलकर्ता से मुलाकात हुई थी। यहाँ उसने उसे एक बार फिर लालच दिया और इस तरह, वह न्यायालय में शादी करने के लिए उसके साथ अंबाला जाने को तैयार हो गई। हालाँकि, जब वे पुराने बस स्टैंड कुरुक्षेत्र पहुँचे, तो वहाँ उसने अपने पिता और कई पुलिसकर्मियों को वहाँ मौजूद पाया, और उसके बाद अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता को करनाल ले जाया गया।

5. 5.7.1996 को अभियोक्त्री पीडब्लू.7 के रूप में न्यायालय में परिक्षित हुई, जिसमें उसने बताया कि 10.5.1995 को, सहमत योजना के अनुसार, वह न्यायालय में शादी करने के लिए अपीलकर्ता के साथ कुरूक्षेत्र जाने के लिए अपने घर से निकली थी। हालाँकि, उसने अपीलकर्ता को उनके द्वारा तय किए गए स्थान पर नहीं पाया था, और इसलिए उसने उसके द्वारा दिए गए नंबर पर उसे फोन किया था। फिर उसे सूचित किया गया कि अपीलकर्ता पहले ही कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुका है और इसलिए, दोपहर 12.00 बजे से 1.30 बजे तक उसका इंतजार किया गया। जब वह आया, तो वह अपीलकर्ता के साथ दोपहर 2.30 बजे बस से कर्ण झील (करनाल) चली गई। यहां, उसे कर्ण झील पर रेस्तरां के पीछे कुछ झाड़ियों में ले जाया गया और उसके बाद अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। उक्त समय पर उसने न तो कोई आपत्ति जताई और न ही कोई शोर-शराबा किया। अभियोक्त्री ने कुरूक्षेत्र जाकर 3-4 दिन रहने के बावजूद उक्त घटना का किसी से जिक्र तक नहीं किया। उसने इस संबंध में बस स्टैंड पर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की। वह अपीलकर्ता के साथ उसके रिश्तेदारों के घर में लगातार रहती रही और वहाँ उसके साथ बलात्कार किया गया। अपीलकर्ता किसी न किसी बहाने से अपनी शादी को टालता रहा। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया।

इस प्रकार वह विश्वविद्यालय के छात्रावास में जाकर रहने लगी और पूछताछ करने पर उसने वार्डन को अपने साथ घटना के बारे में विवरण दिया, जिसने उसके परिवार को सूचित किया। इसके बाद वह कुरूक्षेत्र के बिड़ला मंदिर गईं और यहां उसकी अपीलकर्ता से एक बार फिर मुलाकात हुई। अपीलकर्ता ने उसे अपने साथ अंबाला चलने और वहाँ न्यायालय में शादी करने के लिए मनाने का एक और प्रयास किया। पुराने बस स्टैंड पर पहुंचने पर, उसने वहाँ अपने भाई राजिंदर को पुलिस दल के साथ पाया, जो जीप में उनके साथ करनाल जा रहा था।

6. पीड़िता अभियोक्त्री के पिता बलदेव राज सोनी (पीडब्लू. 8) ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 10.5.1995 को उनकी बेटी गीता घर नहीं आई थी। इसलिए उसने शिकायत दर्ज की और गीता की दोस्त रजनी से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि अपीलकर्ता दीपक उसे कुरुक्षेत्र ले गया था। दिनांक 17.5.1995 को, पुलिस गीता का पता लगाने के लिए उनके साथ कुरूक्षेत्र गई थी, जहां उन्हें अभियोक्त्री और अपीलकर्ता कुरूक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर बैठे हुए मिले थे। दोनों को उन्होंने पकड़ लिया और करनाल ले आए थे।

7. श्रीमति. पी.कांत वशिष्ठ (पीडब्ल्यू.10), सरस्वती भवन कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की वार्डन ने, हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, और पक्षदोही घोषित की गयी, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि अभियोक्त्री गीता को उनके कार्यालय में अश्विनी नाम का एक व्यक्ति जो, इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, लाया था, उसने गीता को उसके कार्यालय में यह कहकर छोड़ दिया था कि उसके माता-पिता को सूचित करेगा कुछ समय बाद उसका भाई आया था और उसे ले गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में उसने अभिकथन किया है कि अभियोक्त्री वास्तव में बिना किसी प्राधिकार/अनुमति के छात्रावास में रुकी थी। वहाँ की एक परिचारिका निर्मला ने उसे बिना किसी अपेक्षित अनुमति के रहने की इजाजत दे दी थी।

8. श्रीमती, कृष्णा चावला (पीडब्लू.3), सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल, करनाल में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता ने न्यायालय के समक्ष गवाही दी है, और स्कूल रजिस्टर से यह साबित किया है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि 26.6.1976 थी।

9. डॉ. (श्रीमती) अमरजीत वाधवा (पीडब्लू.11), मेडिकल ऑफिसर, सरकारी अस्पताल, करनाल, जिन्होंने 17.5.1995 को पीड़िता की जांच की थी, ने कथन किया है कि पीड़िता संभोग में लिप्त थी और उसे इसकी आदत थी।

10. श्री भगवान चंद (पीडब्लू.12), एएसआई, अनुसंधान अधिकारी ने कथन किया है कि 17.5.1995 को पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करने के बाद, वह एक कांस्टेबल के साथ पीड़िता की तलाश के लिए उसके पिता को कुरुक्षेत्र ले गए थे। दोपहर लगभग 12.00 बजे जब वे कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर पहुंचे, तो पीड़िता के पिता ने गीता को बस स्टैंड के एक कोने में अपीलकर्ता दीपक के साथ बैठे देखा और उसके बाद, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उसने यह भी कथन किया है कि उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज किया था।

11. गवाहों के बयानों में तात्विक विरोधाभास, सुधार और अलंकार मौजूद हैं। जिरह में, बलदेव राज सोनी (पीडब्लू.8) ने गवाही दी है कि वह अपने रिश्तेदारों यानी अश्विनी कुमार और सुरिंदर के साथ कुरुक्षेत्र गया था, और कथन किया है कि उस समय उसका बेटा राजिंदर उसके साथ नहीं था। उसने यह नहीं बताया है कि उन्हें किसी छात्रावास के वार्डन से कोई टेलीफोन कॉल आया था, जैसा कि अभियोक्त्री ने सुझाया है। इसके अलावा, अभियोक्त्री ने द.प्र.स. की धारा 164 के तहत अपने बयान में करनाल में कर्ण झील पर अपीलकर्ता के साथ यौन संपर्क में शामिल होने की घटना का उल्लेख नहीं किया है। भगवान चंद (पीडब्लू.12), ने यह उल्लेख नहीं किया है कि जब वे कुरुक्षेत्र से करनाल की यात्रा कर रहे थे तो अभियोक्त्री का कोई रिश्तेदार उनके साथ था।

12. वर्तमान मामले में पीड़िता के पिता बलदेव राज सोनी (पीडब्लू.8) द्वारा भादस की धारा 365 और 366 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अपीलकर्ता

सहित कई लोगों का नाम शामिल है, उन पर अपनी बेटी को बहलाने और गलत तरीके से उसे अज्ञात स्थान पर सदोष परिरोध करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार उसने अपनी बेटी की जान को खतरे की आशंका जताई है।

13. स्वीकृत रूप से अभियोक्त्री ने किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के समक्ष कोई शिकायत नहीं उठाई है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः उसके द्वारा उससे शादी करने के वादे के बदले में उसने अपीलकर्ता की इच्छा के प्रति समर्पण किया है, इस प्रकार, यह प्रश्न उठता है कि क्या, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, अपीलकर्ता का शुरू से ही उसे धोखा देने का इरादा था जब उसने पीड़िता को करनाल से अपने साथ कुरूक्षेत्र जाने के लिए कहा था।

14. मामले के निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) उक्त घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 19 वर्ष थी।

(ii) उसका अपीलकर्ता के प्रति झुकाव था और वह स्वेच्छा से उसके साथ शादी करने के लिए कुरूक्षेत्र गई थी

(iii) अपीलकर्ता उसे इस बात का आश्वासन दे रहा था कि वह उससे शादी करेगा।

(iv) दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध स्पष्ट रूप से अभियोक्त्री की सहमति से विकसित हुए थे, क्योंकि न तो किसी प्रतिरोध का मामला था, न ही उसने इस तथ्य के बावजूद कि वह कई दिनों से अपीलकर्ता के साथ रह रही थी, किसी भी समय कहीं भी कोई शिकायत दर्ज की थी।, और उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की थी।

(v) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्रावास छोड़ने के बाद भी, वह अपीलकर्ता के साथ अंबाला जाने के लिए सहमत हो गई और चली गई, ताकि वह वहाँ उससे शादी कर सके।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'अधिनियम 1872' के रूप में संदर्भित) की धारा 114.ए में प्रावधान है कि यदि अभियोक्त्री कथन करती है कि उसने अपनी सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा की उसने वास्तव में ऐसी सहमति नहीं दी थी। मौजूदा मामले के तथ्य इस बात की अनुमति नहीं देते है कि अधिनियम 1872 की धारा 114.ए के प्रावधानों को लागू किया जाए। इसलिए, यहां एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उसकी सहमति शादी के झूठे वादे पर ली गई थी। इस प्रकार, अधिनियम 1872 की धारा 90 के प्रावधानों के साथ-साथ भादस की धारा 417, 375 और 376 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिनियम 1872 की धारा 90 में प्रावधान है कि तथ्य की गलतफहमी के तहत दी गई कोई भी सहमति वैध सहमति नहीं होगी। जहां तक भादस की धारा 375 के प्रावधानों का सवाल है, इसे वैध सहमति नहीं माना जाएगा और इस प्रकार, ऐसा शारीरिक संबंध बलात्कार करने के समान होगा।

16. इस न्यायालय ने उदय बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2003 एससी 1639 दिलीप सिंह उर्फ दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2005 एससी 203; येदला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 11 एससीसी 615; और प्रदीप कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, एआईआर 2007 एससी 3059, के मामलों में इसमें शामिल विवाद विषय पर विस्तार से विचार किया; और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जहाँ तक अभियुक्त के अपराध का संबंध है इस घटना में आरोपी का वादा झूठा नहीं है और अभियोक्त्री को इसमें यौन कृत्य में शामिल होने के लिए

बहकाने के एकमात्र इरादे से नहीं किया गया है। ऐसा यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार, यह केवल यही माना जाएगा कि जहां अभियोक्त्री इस हद तक तथ्य की गलतफहमी के तहत कि आरोपी उससे शादी करने की संभावना रखता है, आरोपी की वासना के आगे झुक जाती है, ऐसे कपटपूर्ण कृत्य को अब तक सहमति से नहीं कहा जा सकता है।

17. बलात्कार किसी भी समाज में सबसे नैतिक और शारीरिक रूप से निंदनीय अपराध है, क्योंकि यह पीड़िता के शरीर दिमाग और गोपनीयता पर हमला है। जहां एक हत्यारा पीड़ित के शारीरिक ढांचे को नष्ट कर देता है, वहीं एक बलात्कारी एक असहाय महिला की आत्मा को अपमानित और अपवित्र कर देता है। बलात्कार एक महिला को जानवर बना देता है, क्योंकि यह उसके जीवन की मूल भावना को झकझोर देता है। किसी भी तरह से बलात्कार पीड़िता को सह-अपराधी नहीं कहा जा सकता। बलात्कार पीड़िता के जीवन पर एक स्थायी निशान छोड़ देता है, और इसलिए बलात्कार पीड़िता को एक घायल गवाह की तुलना में ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। बलात्कार पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है और पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सबसे घृणित अपराध होने के नाते, बलात्कार एक महिला के सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर आघात के समान है, और उसके सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों को ठेस पहुँचाता है। यह पीड़िता को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे उस पर अमिट छाप पड़ जाती हैं।

18. सहमति अभिव्यक्त या निहित हो सकती है, जबरदस्ती या गुमराह हो सकती है, स्वेच्छा से या धोखे से प्राप्त की जा सकती है।सहमति किसी कार्य का एक कारण है, जिसमें विचार-विमर्श शामिल है, दिमाग एक तराजू की तरह प्रत्येक पक्ष के अच्छे और बुरे को तौलता है बलात्कार और सहमति से शारीरिक संबंध के बीच स्पष्ट

अंतर है और इस प्रकार न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक चरण में ही शादी का झूठा वादा किया था और क्या इसमें शामिल सहमति यौन संबंध की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह समझने के बाद दी गई थी। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री आरोपी के प्रति अपने प्यार और आशक्ति के कारण संभोग करने के लिए सहमत हो, न कि केवल आरोपी द्वारा उसके साथ की गई गलत प्रस्तुति के कारण, या जहां, एक आरोपी उन परिस्थितियों के कारण जिसके उन परिस्थितियों के कारण जिनकी उसने कल्पना नहीं की थी, या जो उसके नियंत्रण से परे थी, ऐसा करने का हर इरादा होने के बावजूद, वह उससे शादी करने में असमर्थ था। ऐसे मामलों में अलग तरह से व्यवहाँर किया जाना चाहिए। किसी आरोपी को बलात्कार के लिए तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि आरोपी का इरादा दुर्भावनापूर्ण था और उसके छुपे हुए इरादे थे।

19. दिलीप सिंह (उपर वर्णित मामले) में, इसे निम्नानुसार देखा गया है:

> "20. धारा 90 के पहले भाग में निर्धारित कारक पीड़ित के दृष्टिकोण से हैं। धारा 90 का दूसरा भाग आरोपी के दृष्टिकोण से संबंधित प्रावधान को अधिनियमित करता है। इसमें परिकल्पना की गई है कि आरोपी को भी यह जानकारी है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि सहमति क्षति के डर या तथ्य की गलतफहमी के परिणामस्वरूप पीड़ित द्वारा सहमति दी गई थी। इस प्रकार, दूसरा भाग उस व्यक्ति के ज्ञान या उचित विश्वास पर जोर देता है जो दुषित सहमति प्राप्त करता है। दोनों भागों की आवश्यकताओ को संचयी रूप से एक साथ संतुष्ट किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को यह देखना होगा कि सहमति देने वाले व्यक्ति ने क्षति

के डर से या तथ्य की गलतफहमी के तहत सहमति दी थी और न्यायालय को इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कथित अपराधी, इस तथ्य से अवगत है या उसके पास ऐसा सोचने का कारण होना चाहिए, की डर या ग़लतफ़हमी के कारण, सहमति नहीं दी गई होगी। यह धारा 90 की योजना है जो नकारात्मक शब्दावली में समाहित है।"

20. इस न्यायालय ने, प्रदीप कुमार वर्मा (उपर वर्णित मामले) का फैसला करते समय, एन. जलाडु, आरई आईएलआर (1913) 36 मद्रास 453 में दिए गए मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह देखा गया है:

"हमारी राय है कि अभिव्यक्ति "तथ्य की गलतफहमी के तहत" इतनी व्यापक है कि इसमें उन सभी मामलों को शामिल किया जा सकता है जहां सहमति गलत बयानी द्वारा प्राप्त की गई है; गलत बयानी को उन तथ्यों के बारे में गलतफहमी पैदा करने वाला माना जाना चाहिए जिनके संदर्भ में सहमति दी गयी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दृष्टांत(डी) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अमुक आशय रखता है को एक तथ्य के रूप में माना जाता है। इसलिए, यहां जिस तथ्य के बारे में दूसरे और तीसरे अभियोजन पक्ष के गवाहों को गलतफहमी का सामना करना पड़ा, वह तथ्य यह था कि दूसरे आरोपी का इरादा लड़की से शादी करने का था..... "इस प्रकार..... यदि उस व्यक्ति की सहमति जिसके कब्जे से लड़की मिली है ली गयी है, धोखाधड़ी से प्राप्त की गयी है, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध लेना माना जाता है।" हालांकि अनुबंधों के मामलों में जबरदस्ती या धोखाधड़ी से

प्राप्त सहमति केवल उससे प्रभावित पक्ष द्वारा रद्व की जा सकती है, भादस की धारा 90 का प्रभाव यह है कि आपराधिक कानून के तहत ऐसी सहमति का अन्यथा जो अपराध होगा उसे उचित ठहराने के लिए लाभ नहीं उठाया जा सकता है।"

21. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होनी चाहिए कि प्रासंगिक समय पर, अर्थात्। शुरुआती चरण में, ही आरोपी का पीड़िता से शादी करने के अपने वादे को निभाने का कोई इरादा नहीं था। निस्संदेह, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब एक व्यक्ति नेक इरादा रखता हो परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से शादी करने में असमर्थ हो। भविष्य की अनिश्चित तारीख के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने में विफलता, के कारण जो उपलब्ध साक्ष्यों से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, हमेशा तथ्य की गलत धारणा नहीं होती है। गलत धारणा शब्द के अर्थ में आने के लिए वास्तव में, तथ्य की तत्काल प्रासंगिकता होनी चाहिए।" ऐसी स्थिति में भादस की धारा 90 की उपधारणा को किसी लड़की के कृत्य को पूरी तरह से माफ करने और दूसरे पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है।दूसरा, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त नहीं हो जाता है कि शुरू से ही, आरोपी ने वास्तव में उससे शादी करने का कभी इरादा नहीं किया था।

22. हस्तगत मामला तथ्यात्मक रूप से उदय (उपर वर्णित मामले) के समान है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद पाए गए:

(i) अभियोक्त्री की उम्र 19 वर्ष थी और उसके पास इससे जुड़े महत्व और नैतिकता को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि और परिपक्वता थी। जिस कार्य के लिए वह सहमति दे रही थी।

(ii) वह इस तथ्य से अवगत थी कि जाति कारक सहित विभिन्न कारणों से उसकी शादी नहीं हो सकती है।

(iii) अभियुक्त पर यह आरोप लगाना मुश्किल था कि उसे इस तथ्य का ज्ञान था कि अभियोक्त्री ने तथ्य की गलतफहमी के परिणामस्वरूप सहमति दी थी, जो उससे शादी करने के उसके वादे से उत्पन्न हुई थी।

(iv) निर्णायक रूप से यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता का अभियोक्त्री से शादी करने का कभी इरादा नहीं था।

23. निष्कर्षतः पीड़िता ने अपीलकर्ता से शादी करने के लिए अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया था। प्रासंगिक समय पर उसकी उम्र 19 वर्ष थी और इसलिए, वह अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी से जुड़ी जटिलताओं और मुद्दों को समझने में सक्षम थी। उसके द्वारा कथित की गई घटनाओं के संस्करण के अनुसार, अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता को उसके द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल किया था, यह पूछने के लिए कि वह उससे उस स्थान पर क्यों नहीं मिला जो उनके द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था। उसने काफी देर तक उसका इंतजार भी किया और जब वह आखिरकार आ गया तो वह उसके साथ कर्ण झील पर गई जहां उन्होंने संभोग किया। उसने इस स्तर पर कोई आपत्ति नहीं जताई और किसी से कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद, वह अपीलकर्ता के साथ कुरुक्षेत्र भी गई, जहां वह उसके रिश्तेदारों के साथ रही। यहां भी, अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ अंतरंग हो गयी। फिर, किसी कारण से, वह अवैध रूप से कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने चली गई और एक बार फिर बिड़ला मंदिर में अपीलकर्ता के संपर्क में आई। इसके बाद, वह अंबाला जाने के लिए अपीलकर्ता के साथ कुरूक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर भी गई, ताकि वे दोनों अंबाला में न्यायालय में शादी कर सकें। हालांकि, यहां उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया।

24. यदि अभियोक्त्री वास्तव में अपीलकर्ता से शादी करने के लिए अंबाला जा रही थी, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पूरी तरह से स्थापित है, ऐसे में कोई भी यह समझने में असमर्थ है कि किस आधार पर अभियोक्त्री द्वारा शादी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया गया है। उपर्युक्त तथ्य की स्थिति के आलोक में कोई भी उन परिस्थितियों को समझने में असमर्थ है जिनमें अपीलकर्ता के खिलाफ धोखे/ब्लात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।

25. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता, जो पहले ही 3 वर्ष से अधिक सजा काट चुका है, संदेह का लाभ पाने का हकदार है। अतः अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। उसकी नीचे के न्यायालयों द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उनके जमानत बंधपत्र खारिज किये जाते हैं।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **श्री देवकुमार खत्री** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।